लोकतंत्र की आत्मा है - संवाद

हरियाणा संवाद

पाक्षिक : 1 - 15 फरवरी 2023 www.haryanasamvad.gov.in अंक -59

"साहित्य, विज्ञान और कला की साधना स्वाधीन लोगों द्वारा ही होनी चाहिए
: प्रिंस क्रोपाटकिन

G20 भारत 2023 INDIA
जी-20 की बैठकों की तैयारी में जुटा हरियाणा 3

चीनी मिलों में घाटे के बावजूद गन्ने के भाव में बढ़ोतरी 5

सरस्वती महोत्सव शंखनाद, मंत्रोच्चारण व आतिशबाजी के साथ सम्पन्न 8

कर्तव्य पथ से गीता का संदेश

विशेष प्रतिनिधि

गणतंत्र दिवस समारोह में कर्तव्य पथ पर हरियाणा की झांकी ने पूरी दुनिया को श्रीमद्भगवद्गीता के शाश्वत संदेश से रू-ब-रू करवाया। कर्तव्य पथ पर अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव थीम से जुड़ी झांकी के माध्यम से दर्शकों ने भगवान श्रीकृष्ण के विराट स्वरूप के भी दर्शन किये। हरियाणा की झांकी देख दर्शकों ने तालियों के साथ जोरदार स्वागत किया।

झांकी में भगवान श्रीकृष्ण को अर्जुन का सारथी बनकर गीता का ज्ञान देते हुए दिखाया गया। झांकी के अग्रभाग में श्रीकृष्ण के 'विराट स्वरूप' के दर्शन होते हैं, जैसा कि युद्ध भूमि पर उन्होंने अर्जुन के सामने प्रदर्शित किया था। विराट स्वरूप की प्रतिमा में श्री विष्णु के 9 सिर 'क्रमशः अग्नि, नृसिंह, गणेश, शिव, विष्णु, ब्रह्मा, अश्विनी कुमार, हनुमान और परशुराम दिखाए गए। दिव्य सर्प सिर

ढके हुए और श्री विष्णु दाहिने हाथ में तलवार, त्रिशूल, कमल, सुदर्शन चक्र तथा बाएं हाथ में शंख, बरछा, धनुष, नाग, गदा आदि लिए हुए हैं। झांकी के अंतिम भाग में कुरुक्षेत्र युद्ध क्षेत्र में चार घोड़ों के साथ एक भव्य रथ का प्रदर्शन किया गया। कर्तव्य पथ पर हरियाणा की भव्य झांकी अपनी अमिट छाप छोड़ने में कामयाब रही।

भगवान श्रीकृष्ण ने महाभारत युद्ध के मैदान में अर्जुन को श्रीमद्भगवद्गीता का शाश्वत संदेश दिया, इसलिए कुरुक्षेत्र की पहचान गीता की जन्मस्थली के रूप में होती है। गीता की इसी प्रासंगिकता को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका संदेश देश दुनिया तक पहुंचाने का आह्वान किया। इसी कड़ी में मनोहर लाल सरकार ने गीता स्थली को न केवल अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाई अपितु विदेशों में भी 'गीता महोत्सव' आयोजित कर इसके वैश्विक व प्रेरणादायक संदेश को जन-जन तक पहुंचाने का कार्य किया।

व्यवस्था परिवर्तन से हुआ समान विकास

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रदेश का समग्र एवं समान विकास व्यवस्था परिवर्तन से ही संभव था जो उन्होंने विगत आठ साल में करने का प्रयास किया है। उन्होंने 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर जगाधरी में आयोजित समारोह में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद जनसमूह को संबोधित किया।

उन्होंने कहा कि सरकार ने हर व्यक्ति के उत्थान व कल्याण पर ध्यान केन्द्रित किया है, जिसके परिणामस्वरूप प्रदेश में 'ईज ऑफ लिविंग' और 'हैप्पीनेस इंडेक्स' का ग्राफ निरंतर ऊपर उठ रहा है। मुख्यमंत्री ने

नागरिकों से आह्वान किया वे सभी समृद्ध सांस्कृतिक परम्पराओं और उच्च नैतिक मूल्यों का निर्वहन करते हुए राष्ट्रीय एकता एवं अखण्डता के मार्ग पर चलने संकल्प लें।

उन्होंने कहा कि सभी लोग समाज कल्याण में भागीदार बनें, संकल्प लें कि वे जिस योजना के पात्र हैं केवल उसी का फायदा लेंगे। जिसकी पात्रता नहीं है उसका लालच न करें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि योजनाओं का लाभ हर जरुरतमंद परिवार को मिले इसके लिए उनकी सरकार ने आईटी का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया है। इसी वजह से उनकी सरकार को पोर्टल की सरकार कहा जाता है। इसका उन्हें गर्व है कि उन्हें ऐसा कहा जाता है, क्योंकि पोर्टल के माध्यम से ही समाज के हर वर्ग के लोगों को सरल व पारदर्शी ढंग से योजनाओं का लाभ मिल रहा है। अब हर पात्र व्यक्ति को उसका हक मिल रहा है।

उन्होंने कहा कि यह पोर्टल का ही कमाल है कि आज गरीब की बेटी की शादी का शगुन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति एक क्लिक पर सीधे उनके खाते में जा रही है। खाद, बीज, मशीनरी की सब्सिडी, फसल का मुआवजा, फसल खरीद का पैसा एक क्लिक पर किसान के खाते में जाता है। यह भी पोर्टल का ही कमाल है कि अब किसानों को जमीन की फर्द लेने के लिए पटवारियों के चक्कर नहीं काटने पड़ते। एक क्लिक पर ही अपनी फर्द निकाल सकते हैं। अब विदेश जाने के इच्छुक युवा अपना पासपोर्ट बनवाने के लिए जरूरी दस्तावेज घर बैठे ऑनलाइन ही अपलोड कर सकते हैं।

प्रगति के पथ पर हरियाणा

राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर कुरुक्षेत्र में कहा कि गणतंत्र दिवस के साथ देशभक्तों के त्याग, तप और बलिदान की एक लम्बी गौरव गाथा जुड़ी है। इस देश के वीरों, स्वतंत्रता सेनानियों और 'क्रांतिकारियों के बलिदान के कारण ही आज सभी भारतवासी खुली हवा में सांस ले रहे है, इन शूरवीरों के बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है।

उन्होंने कहा कि श्रीमद्भागवत गीता की इस पावन धरा पर धर्म की रक्षा के लिए पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध में भगवान श्रीकृष्ण ने गीता उपदेश देकर युद्ध में धर्म की जीत करवाई और पूरी मानवता को कर्म, कर्तव्य, कल्याण, सत्य, समानता का संदेश दिया।

उन्होंने कहा कि आज संविधान के अनुरूप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश दिन दोगुनी-रात चौगुनी प्रगति कर रहा है। इस वर्ष देश में स्वतंत्रता सेनानियों को विशेष सम्मान देने के साथ-साथ आगामी 25 सालों के लिए एक विजन व रूपरेखा भी बनाई जा रही है ताकि 2047 में आजादी के सौ वर्ष पूरे होने पर भारत पूरी दुनिया को नेतृत्व प्रदान करें। उन्होंने यह भी कहा कि हरियाणा की मनोहर सरकार ने प्रगति के अनेक प्रतिमान स्थापित किए हैं जो देश के अन्य राज्यों के लिए भी प्रेरणादायक साबित हो रहे हैं।

स्वतंत्रता सेनानियों के परिजन सम्मानित: राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों दलीप कौर, सुशीला कुमारी, संतोष कुमारी, जसबीर कौर, रामदास गोयल, सतपाल सिंह, शहीद वीर सैनिकों के परिजनों में हरभजन कौर, सुरजीत कौर, कृष्णा देवी, दलीप कौर, ममता शर्मा, पार्वती देवी, धन्नी देवी, प्रेरणा, पुष्पा देवी को मंच से उनकी जगह पर जाकर शॉल व स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया।

संपादकीय

बदलाव आ ही रहे हैं

कार्यक्षमता, कार्यकुशलता व कर्मठता, ये कुछेक विशिष्ट गुण हैं जो किसी भी राष्ट्र या प्रांत के नेता को सुदृढ़ व महान बनाते हैं। इन सब गुणों के साथ-साथ यदि पारदर्शिता व राजनैतिक जीवन की स्वच्छता भी शामिल हो तो निश्चित रूप में प्रदेश का भविष्य उज्ज्वल होने लगता है।

वर्तमान मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने जिस दक्षता के साथ पंचायती राज के सशक्ति शरण और ग्रामीण खेले के पुनः प्रारंभ के लिए जो महत्त्वपूर्ण निर्णय हाल ही में लिए हैं, उनके दृष्टिगत यह तय है कि नेतृत्व के समक्ष, लक्ष्य भी तयशुदा है और क्रियान्वयन का मार्ग भी स्पष्ट है।

हाल ही में विभिन्न विभागों का पुनर्गठन भी पूरी प्रशासनिक प्रक्रिया को एकरूपता प्रदान करने के उद्देश्य से ही किया गया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि ग्रामीण क्षेत्र में विकास कार्यों को गति देने के लिए पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) के सदस्यों की शक्ति यों का विकेंद्रीकारण किया गया है।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि पंचायत तीसरी सरकार होती है और इन स्थाई सरकारों को हमने कई अधिकार दिए हैं। पिछली सरकारों ने तो पंचायतों को अधिकार नहीं दिए, लेकिन हमारी सरकार ने पंचायतों को विकास कार्य अपने आप कराने का अधिकार दिया है। पैसा पंचायतों का है, जैसे चाहे खर्च करो। प्रस्ताव पारित करें और अपने क्षेत्र में विकास कार्य करवाएं। आगे भी अधिकार बढ़ाना होगा या पैसा बढ़ाना होगा, तो जैसे ही मांग आएगी, बढ़ा सकते हैं।

पंचायतों को वित्तीय रूप से सशक्त करने के लिए अब स्टाम्प ड्यूटी का 2 प्रतिशत हिस्सा भी पंचायतों को देने की सुविधा शुरू की है। उन्होंने कहा है कि इस वित्त वर्ष के अंतिम तिमाही में गांवों में विकास कार्यों के लिए पंचायतों को 1100 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। पंचायतों को मजबूत करने के लिए इंटर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल भी बनाया है। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने का पैमाना बनाया है। जनता भी पारदर्शिता आने से खुश है। उन्होंने कहा कि गांवों में विकास कार्य तो हो जाते हैं लकिन उनकी संभाल करने के लिए सरपंचों के सहयोग से सेवानिवृत्त लोगों को मिलाकर संभर करें। ग्रामीण अंचल में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए गांव, खण्ड और जिला स्तर पर खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद इन खेलों का आयोजन करवाएंगी। इन प्रतियोगिताओं में 12 प्रकार के खेल सम्मिलित होंगे। ये सब सुखद है और स्वागत-जन्य है।

-डॉ. चन्द्र त्रिखा

समग्र विकास के अहम कदम

मनोज प्रभाकर

गांवों का विकास राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। गांवों में शहरों जैसी सुविधाएं विकसित करने के लिए हरियाणा स्मार्ट ग्राम प्राधिकरण का गठन किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों को डिजिटल बनाने के लिए ग्राम दर्शन पोर्टल शुरू किया है।

24 घण्टे बिजली:

प्रदेश के 92 प्रतिशत गांवों में 24 घण्टे बिजली दी जा रही है। गांवों को लाल डोरा मुक्त करने की हमारी योजना को केन्द्र सरकार ने स्वामित्व योजना के रूप में पूरे देश में लागू किया है। हरियाणा में इस स्कीम के तहत अब तक 6251 गांवों के लगभग 24 लाख 54 हजार से अधिक परिवारों को स्वामित्व कार्ड दिए जा चुके हैं।

पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों का विकेंद्रीकरण:

राज्य सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों का विकेंद्रीकरण कर उन्हें और अधिक स्वायत्तता प्रदान की है। पी.आर.आई. के अपने फंड और ग्रांट-इन-ऐड में से छोटे या बड़े, जिस भी राशि के काम होंगे, उनकी प्रशासनिक स्वीकृति ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के स्तर पर ही होगी। अब फाइलें सरकार के पास नहीं आएंगी। अब ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद अपने स्तर पर ही गांवों का विकास सुनिश्चित कर पाएंगी।

मेडिकल कालेज:

राज्य सरकार का हर जिले में मेडिकल कॉलेज तथा 200 बैड का अस्पताल खोलने का लक्ष्य है। कलस्टर एप्रोच के तहत सभी क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या में स्कूल और 20 किलोमीटर के दायरे में एक कॉलेज खोला गया है। इतना ही नहीं हर क्षेत्र की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए ब्लॉक स्तर पर लघु व मध्यम उद्योगों के कलस्टर स्थापित किए जा रहे हैं। हर विधायक को 5 करोड़ रुपए के विकास कार्य करवाने का अधिकार दिया है।

एनईपी को वर्ष 2025 तक लागू करने का लक्ष्य:

भावी पीढ़ी को संस्कार-युक्त व रोजगारपरक शिक्षा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 लागू की गई है। हरियाणा में एनईपी को वर्ष 2025 तक पूर्ण रूप से लागू करने का लक्ष्य रखा है। प्रदेश में के.जी. से लेकर पी.जी. तक की शिक्षा एक ही परिसर में देने की अवधारणा पर कार्य किया जा रहा है। प्राइवेट स्कूलों की तर्ज़ पर प्रदेश में 126 नये संस्कृति मॉडल स्कूल खोले गये हैं। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 10वीं व 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को लगभग 6 लाख टैबलेट मुफ्त दिए हैं।

रोजगार के लिए पात्रता परीक्षा :

गरीब के बच्चे को भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ने का अवसर देने के लिए हमने चिराग योजना शुरू की गई है। इसमें उसकी स्कूल फीस सरकार द्वारा दी जा रही है। एकल पंजीकरण शुरू किया है। बार-बार प्रतियोगी परीक्षा से निजात दिलाने के लिए कॉमन पात्रता परीक्षा का प्रावधान किया है। जहां पिछले दिनों ग्रुप-सी के लिए यह परीक्षा आयोजित की गई है। ग्रुप डी के लिए सीईटी परीक्षा जल्द आयोजित होगी।

पासपोर्ट सुविधा:

विदेशों में शिक्षा तथा रोजगार के अवसर तलाश रहे विद्यार्थियों के लिए कॉलेजों व पॉलीटेक्निक्स में निःशुल्क पासपोर्ट बनवाने की सुविधा शुरू की है। विदेशों में युवाओं को शिक्षा व रोजगार दिलाने और निवेश आकर्षित करने के लिए विदेश सहयोग विभाग बनाया गया है।

टोहानावासियों को 580 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात

गांव रसूलपुर में मेडिकल कॉलेज व जाखल में नर्सिंग कॉलेज खोलने की घोषणा

मुख्यमंत्री मनोहर लाल नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती पर विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली द्वारा गांव बिढ़ाई खेड़ा में आयोजित प्रगति रैली के दौरान घोषणा करते हुए कहा कि टोहानावासियों को कुल 580 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी है। इनमें से 272 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास है। राजकीय महाविद्यालय, टोहाना को शहर की सीमा से बाहर स्थापित करने की घोषणा करते हुऐ कहा कि जहां कहीं भी 15-20 एकड़ जमीन उपलब्ध होगी, वहां कॉलेज स्थापित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायत तीसरी सरकार होती है और इन स्थाई सरकारों को हमने कई अधिकार दिए हैं। पिछली सरकारों ने तो पंचायतों को अधिकार नहीं दिए, लेकिन हमारी सरकार ने पंचायतों को विकास कार्य अपने आप कराने का अधिकार दिया है। पैसा पंचायतों का है, जैसे चाहे खर्च करो। प्रस्ताव पारित करें और अपने क्षेत्र में विकास कार्य करवाएं। आगे भी अधिकार बढ़ाना होगा या पैसा बढ़ाना होगा, तो जैसे ही मांग आएगी, बढ़ा सकते हैं। इस वित्त वर्ष के अंतिम तिमाही में गांवों में विकास कार्यों के लिए पंचायतों को 1,100 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है।

उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि आज हरियाणा प्रगति के पथ पर है। ई-भूमि पोर्टल पर जमीन भू-मालिकों की सहमति से खरीद रहे हैं। हाल ही में टोहाना के नये बस अड्डा के लिए छह एकड़ भूमि ई-पोर्टल से खरीदी है। उन्होंने कहा कि बिढ़ाई खेड़ा का सामुदायिक केंद्र पूरे प्रदेश के लिए एक मॉडल है और इसी तर्ज़ पर गांवों में सामाजिक समारोह के लिए सामुदायिक केंद्रों का निर्माण करवाया जाएगा। विकास एवं पंचायत मंत्री व रैली के संयोजक देवेंद्र सिंह बबली ने कहा कि आज भाजपा-जजपा एक साझा विजन वाली सरकार है। पहले की सरकारों में टोहाना के साथ भेदभाव होता रहा है। नहरों की नगरी व देशभक्तों की धरती पर राजनीतिक बदलाव आया है तो विकास की बयार शुरू हो गई है।

सलाहकार संपादक : डा. चंद्र त्रिखा
सह संपादक : मनोज प्रभाकर
स्टाफ राइटर : संगीता शर्मा
संपादन सहायक : सुरेंद्र बांसल
चित्रांकन एवं डिज़ाइन : गुरप्रीत सिंह
डिजिटल सपोर्ट : विकास डांगी

परियोजनाओं का किया उद्घाटन व शिलान्यास

सिंचाई विभाग की 6 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत की बलियाला गेस्ट हाउस में स्विमिंग पूल और सौंदर्यकरण के कार्य का उद्घाटन, पांच करोड़ 65 लाख रुपए की लागत के कल्पना चावला पार्क, 58 करोड़ दस लाख 70 हजार रुपए की लागत के हिसार से रतिया रोड के बाइपास, एक करोड़ 92 लाख 70 हजार रुपए की लागत के वाटर वर्क्स, एक करोड़ 63 लाख 75 हजार रुपए की लागत का गांव डूल्ट में वाटर वर्क्स, गांव नाढ़ोड़ी में दो करोड़ 14 लाख 54 हजार रुपए की लागत का वाटर वर्क्स, एक करोड़ 72 लाख 70 हजार रुपए की लागत के गांव पारता में वाटर वर्क्स का एक्सटेंशन कार्य का उद्घाटन किया। 11 करोड़ 32 लाख रुपए की लागत से बनने वाले गांव भिमेवाला में जलभराव और बाढ़ राहत कार्यों का शिलान्यास किया। इसी प्रकार से 131 करोड़ 87 लाख 72 हजार रुपए की लागत से बनने वाले नागरिक अस्पताल टोहाना, पांच करोड़ 50 लाख रुपए की लागत के पंचायत भवन टोहाना, 16 करोड़ 60 लाख 98 हजार रुपए की लागत से बनने वाले टोहाना के नये बस अड्डा की आधारशिला रखी गई है। गांव समैण में 13 करोड़ 89 लाख 87 हजार रुपए, गांव हंसेवाला में तीन करोड़ 30 लाख 78 हजार रुपए, गांव ठरवा में चार करोड़ 58 लाख 63 हजार रुपए, गांव कमालवाला में एक करोड़ 73 लाख 68 हजार रुपए के वाटर वर्क्स की भी आधारशिला रखी। इसके अलावा, पांच करोड़ 45 लाख 98 हजार रुपए की लागत से जाखल में पीने के पानी की सप्लाई कार्य तथा फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र के गांव शेखुपुर दड़ौली के दो करोड़ सात लाख रुपए की लागत के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के भवन की भी आधारशिला रखी।

हरियाणा सरकार ने जवाहर सिंह यादव को एक बार फिर मुख्यमंत्री का विशेष कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा इस संबंध में आदेश जारी किए गए ।

'वन जिला-वन उत्पाद' योजना की तर्ज़ पर हरियाणा के 142 ब्लॉकों में 'वन ब्लॉक-वन प्रोडक्ट' के तहत उद्योग लगाए जाएंगे तथा यहां से उत्पादित वस्तुएं देश-विदेश में भेजी जाएंगी: दुष्यंत चौटाला

वसुधैव कुटुम्बकम के लिए अतिथि देवो भवः

जी-20 की बैठकों की तैयारी में जुटा हरियाणा

संगीता शर्मा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत को जी-20 की अध्यक्षता करने का सुनहरा अवसर मिला है। 18वां शिखर सम्मेलन-2023 भारत की अध्यक्षता में 1 दिसंबर, 2022 से 30 नवंबर, 2023 तक आयोजित किया जा रहा है। अलग-अलग राज यों में जी-20 सदस्य देशों के प्रतिनिधि मंडल विशेष मुद्दों में बैठकें आयोजित कर रहा है। भारत का जी-20 अध्यक्षता का विषय - वसुधैव कुटुम्बकम या एक पृथ्वी एक कुटुंब एक भविष्य - महा उपनिषद् के प्राचीन संस्कृत पाठ से लिया गया है।

ग्रुप ऑफ ट्वेंटी (जी-20) अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच है। यह सभी प्रमुख अंतरराष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों पर वैश्विक संरचना और अधिशासन निर्धारित करने तथा उसे मज़बूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

संयुक्त राष्ट्र संघ के सतत विकास लक्ष्य-2030 में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले हरियाणा राज्य को जी-20 शिखर सम्मेलन की बैठकें आयोजित करने का जो सुअवसर मिला है, उसके सफल आयोजन के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्वयं कमान संभाल ली है। अनेक स्तर पर उच्चाधिकारियों की बैठकें आयोजित कर इसके सफल आयोजन के लिए सभी पुख़्ता प्रबंध समय पर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। गर्व की बात यह है कि जी-20 शिखर सम्मेलन की कुछ बैठकें गुरुग्राम में हो रही हैं। जी-20 सदस्य देशों के शिष्टमंडल के हरियाणा आगमन पर अतिथि देवो भव् की भावना से प्रदेश सरकार उनका आतिथ्य सत्कार करेगी। जी-20 शिखर सम्मेलन के अंतर्गत 1 से 3 मार्च तक गुरुग्राम में एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक होगी। इस बार पुरी दुनिया की नजर भारत पर है, वहीं गुरुग्राम, जहां दुनिया की 500 फॉर्चयून कंपनियों के कॉरपोरेट ऑफिस स्थापित है, उसके माध्यम से हरियाणा के लिए भी यह वैश्विक स्तर पर पुनः अपनी पहचान स्थापपित करने का अनोखा अवसर है।

हरियाणवी संस्कृति और खान-पान से होंगे रूबरू

गुरुग्राम में जहां एक ओर इन बैठकों के माध्यम से ग्लोबल वर्ल्ड की झलक दिखेगी, वहीं दूसरी ओर विदेशी मेहमानों को हरियाणा की समृद्ध संस्कृति को भी करीब से देखने व जानने का मौका मिलेगा। मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार अधिकारियों ने इसके लिए अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। जी-20 सदस्य देशों के प्रतिनिधियों को गुरुग्राम के सेक्टर-29 में स्थित म्यूजियो कैमरा (म्यूजियम) का भी दौरा करवाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। यह अनूठा म्यूजियम काफ़ी रोचक जानकारियों से परिपूर्ण है। इसके अलावा, सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य का भी भ्रमण करवाना प्रस्तावित है। इस विशाल प्राकृतिक झील में साइबेरियन पक्षियों की लगभग 100 प्रजातियां आती हैं, जो मुख्य आकृषण का केंद्र है।

कला व संस्कृति की झलक

हरियाणा की पहचान बन चुके अंतरराष्ट्रीय सूरजकुंड शिल्प मेले के माध्यम से भी जी-20 सदस्य देशों के प्रतिनिधियों को देश-विदेश के कलाकारों की कलाकृतियां, हथकरघा, हस्तशिल्प और सांस्कृतिक ताने-बाने की समृद्धि और विविधता देखने को मिलेगी। इसके साथ-साथ सरकार ने सदस्य देशों के प्रतिनिधियों को झज्जर के प्रतापगढ़ फार्म का दौरा करवाने की भी योजना बनाई है। इस फार्म में मेहमानों को हरियाणा के पारंपरिक जनजीवन पर आधारित खेल-कूद, कला संस्कृति, खान-पान, कृषि, बागवानी व पशुपालन से जुड़ी गतिविधियों को देखने का मौका मिलेगा। इसके अतिरिक्त, हरियाणा की विकास गाथा व सांस्कृतिक विरासत को थीम कॉर्नर के माध्यम से प्रदर्शित भी किया जाएगा।

जनभागीदारी अभियान

जी-20 शिखर सम्मेलन को एक जनभागीदारी अभियान बनाने के लिए राज्य सरकार का प्रयास है। इसके लिए उच्च शिक्षा विभाग द्वारा फरवरी माह के दौरान विश्वविद्यालयों तथा कॉलेजों में भारत की जी-20 अध्यक्षता व गुरुग्राम में एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक विषयों पर सेमिनार, निबंध लेखन, प्रतियोगिताएं व अन्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इससे युवाओं, विशेषकर स्कूल, कॉलेजों के विद्यार्थियों को विश्व में जी-20 देशों के महत्व व भूमिका के बारे जानकारी मिलेगी। इसके अलावा, सांस्कृतिक टीमों द्वारा नुक्कड़ नाटक भी प्रदर्शित किए जाएंगे। इस प्रकार, इस शिखर सम्मेलन को एक जनभागीदारी अभियान बनाने का लक्ष्य पूरा होगा।

जी-20 समिट

जी-20 को 'ग्रुप ऑफ ट्वेंटी' भी कहा जाता है। जी-20 में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, ब्रिटेन, अमेरिका और यूरोपीय संघ (ईयू) शामिल हैं। यह वैश्विक आर्थिक सहयोग का एक प्रभावशाली संगठन है। यह वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का लगभग 85 प्रतिशत, वैश्विक व्यापार का 75 प्रतिशत से अधिक और विश्व की लगभग दो-तिहाई आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। जी-20 शिखर सम्मेलन में इसके नेता हर साल जुटते हैं और वैश्विक अर्थव्यवस्था को कैसे आगे बढ़ाया जाए इस पर चर्चा करते हैं। इसका गठन साल 1999 में हुआ था। साथ ही यह एक मंत्रिस्तरीय मंच है जिसे जी-7 द्वारा विकसित एवं विकासशील दोनों अर्थव्यवस्थाओं के सहयोग से गठित किया गया था।

आर्थिक सहयोग है मकसद

इस मंच का सबसे बड़ा मकसद आर्थिक सहयोग है। समूह आर्थिक ढांचे पर काम करने के साथ-साथ आर्थिक स्थिरता, जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दे पर भी बातचीत करता है। इसके केंद्र में आर्थिक स्थिति को कैसे स्थिर और बरकरार रखें, होता है। यह मंच विश्व के बदलते हुए परिदृश्य को भी ध्यान में रखता है और इससे जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी ध्यान केंद्रित करता है। इसमें व्यापार, कृषि, रोज़गार, ऊर्जा, भ्रष्टाचार के खिलाफ़ लड़ाई, आतंकवाद जैसे मुद्दे भी शामिल हैं।

भारत के लिए क्यों अहम

इस मंच की सबसे बड़ी बात है हर साल शिखर सम्मेलन में दुनिया के कई देशों के शीर्ष नेताओं की आपस में मुलाकात होती है। साथ ही इस साल भारत जी-20 की अध्यक्षता ग्रहण कर रहा है। भारत के सामने इसे लेकर कठिन चुनौतियां हैं। भारत की जी-20 प्राथमिकताओं में समावेशी, न्यायसंगत और सतत विकास, महिला सशक्तिकरण, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा, और तकनीक-सक्षम विकास, जलवायु वित्तपोषण, वैश्विक खाद्य सुरक्षा और ऊर्जा सुरक्षा, अन्य शामिल हैं। जी-20 समिट में इस बार के दुनिया के शीर्ष नेता आपस में मुलाकात करेंगे। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि भारत कई व्यापार समझौतों पर अलग-अलग देशों से बात कर सकता है। शिखर सम्मेलन से इतर मोदी कई नेताओं के साथ अलग-अलग द्विपक्षीय बैठक करेंगे।

एक वर्ष के लिए जी-20

जी- 20 अध्यक्षता के तहत एक वर्ष के लिए जी-20 एजेंडा का संचालन किया जाता है और शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। इसमें दो समानांतर ट्रैक होते हैं: वित्त ट्रैक और शेरपा ट्रैक। वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक के गवर्नर वित्त ट्रैक का नेतृत्व करते हैं जबकि शेरपा ट्रैक का नेतृत्व शेरपा करते हैं। शेरपा पक्ष की ओर से जी-20 प्रक्रिया का समन्वय सदस्य देशों के शेरपाओं द्वारा किया जाता है, जो नेताओं के निजी प्रतिनिधि होते हैं। वित्त ट्रैक का नेतृत्व सदस्य देशों के वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक गवर्नर करते हैं। दो ट्रैक के भीतर, विषयगत रूप से उन्मुख कार्य समूह हैं जिनमें सदस्यों के संबंधित मंत्रालयों के साथ-साथ आमंत्रित/अतिथि देशों और विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि भाग लेते हैं। ये कार्य समूह प्रत्येक अध्यक्षता के पूरे कार्यकाल में नियमित बैठकें करते हैं। शेरपा वर्ष के दौरान हुई वार्ता का पर्यवेक्षण करते हैं, शिखर सम्मेलन के लिए एजेंडा आइटम पर चर्चा करते हैं और जी-20 के मूल कार्य का समन्वय करते हैं।

जी-20 लोगो भारत के राष्ट्रीय ध्वज के जीवंत रंगों - केसरिया, सफेद और हरे, एवं नीले रंग से प्रेरित है। इसमें भारत के राष्ट्रीय पुष्पय कमल को पृथ्वी ग्रह के साथ प्रस्तुत किया गया है जो चुनौतियों के बीच विकास को दर्शाता है। पृथ्वी जीवन के प्रति भारत के पर्यावरण अनुकूल दृष्टिकोण को दर्शाती है, जिसका प्रकृति के साथ पूर्ण सामंजस्य है। जी-20 लोगो के नीचे देवनागरी लिपि में भारत लिखा है।

भारत की जी-20 की अध्यक्षता दुनिया में एकता की इस सार्वभौमिक भावना को बढ़ावा देने की ओर काम करेगी। इसलिए हमारी थीम - एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य है। आज हमारे पास दुनिया के सभी लोगों की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त साधन हैं। जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद और महामारी जैसी बड़ी चुनौतियों का समाधान आपस में लड़कर नहीं, बल्कि मिलकर ही निकाला जा सकता है।

-नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

जी-20 शिखर सम्मेलन की सफलता के लिये सभी प्रबंध समय पर सुनिश्चित किये जाएंगे ताकि भारत की 'अतिथि देवो भव' के साथ हरियाणा की समृद्ध संस्कृति की अमिट छाप और गुरुग्राम-एक ग्लोबल सिटी का संदेश भी सभी जी-20 सदस्य देशों में जाए। विभिन्न देशों के शिष्टमंडल का हरियाणा में आगमन होगा तो उन्हें राज्य की संस्कृति व विरासत से परिचय करवाने हेतु विशेष प्रबंध किये जाएंगे।

-मनोहर लाल, मुख्यमंत्री, हरियाणा

खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए पंचायती स्तर पर खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। इन प्रतियोगिताओं में 12 प्रकार के खेल होंगेः मुख्यमंत्री मनोहर लाल

हरियाणा सरकार ने निर्णय लिया है कि भविष्य में सरकारी कर्मचारी की पुनर्नियुक्ति के मामले में दो वर्ष से अधिक सेवा के बाद पुनः विचार नहीं किया जाएगा।

ग्रामीण विकास से होगा समुचित विकास

सीएम ने ग्राम सरंक्षकों से किया सीधा संवाद

विशेष प्रतिनिधि

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 'ग्राम सरंक्षक संवाद कार्यक्रम' के तहत ऑडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ग्राम-संरक्षकों से संवाद करते हुए उन्हें ज़मीनी स्तर पर गांवों में हो रहे कार्यों का मौके पर जाकर आकलन कर सरकार को फीडबैक रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए, ताकि विकास कार्यों से जुड़े संबंधित विभागों को इसकी जानकारी दी जा सके। यदि कहीं कोई कमी होगी तो उसमें तुरंत सुधार किया जाएगा। ग्राम संरक्षकों को गांवों को परिवार मानकर सेवा भाव से कार्य करना होगा।

संवाद कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने सभी 22 जिलों के श्रेणी- 1 के अधिकारी, जो ग्राम संरक्षक नामित किए गए हैं, से उनके द्वारा निरीक्षण किए गए कार्यों की जानकारी ली। मनोहर लाल ने कहा कि विकास का रास्ता गांव से होकर जाता है, गांवों का विकास होगा, तभी प्रदेश का समुचित विकास होगा। इसलिए संरक्षकों को विशेष रूप से गांवों में हो रहे विकास कार्यों का निरीक्षण करें। मुख्य रूप से पार्क एवं व्यायामशाला, आंगनवाडी केंद्रों, शिवधाम नवीनीकरण योजना के तहत शमशान घाट में चारदीवारी, पानी की व्यवस्था, शेड और पक्का रास्ता आदि कार्यों की समीक्षा कर रिपोर्ट intrahry.gov.in पोर्टल पर अपलोड करें। इसके अलावा, ग्राम संरक्षक गांवों में 25 हजार से कम वार्षिक आय वाले परिवारों से भी संपर्क करें और अपनी रिपोर्ट भेजें, ताकि सरकार ऐसे परिवारों को मुख्य धारा में लाने के लिए विशेष प्रयास कर सके। उन्होंने कहा कि 'मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना' के माध्यम से विशेष कैंप लगवाकर ऐसे परिवारों के सदस्यों को रोज़गार मुहैया करवाएंगे, ताकि उनके जीवन स्तर में सुधार हो सके।

उन्होंने कहा कि वर्ष में कम से कम छह बार ग्राम सभाओं की बैठकों का आयोजन होना चाहिए। ग्राम संरक्षक सरपंचों के साथ समन्वय स्थापित कर इन सभाओं का आयोजन कर ग्रामीणों को सरकार की अन्य योजनाओं से भी अवगत करवाएं व उन्हें ज़ागरूक करें।

266 योग सहायकों को जॉब ऑफर:

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का एक हजार पार्क एवं व्यायामशालाएं स्थापित करने का लक्ष्य है, अधिकतर गांवों में व्यायामशालाएं बनाई जा चुकी हैं। इन पार्क एवं व्यायामशालाओं में लोग व्यायाम व योग कर शरीर को स्वस्थ बना सकते हैं। इसके लिए सरकार द्वारा इन पार्क एवं व्यायाशालाओं में योग सहायकों की नियुक्ति की जा रही है। इससे पूर्व, मुख्यमंत्री ने आज हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से 266 योग सहायकों को ऑनलाइन जॉब ऑफर भेजे। लगभग 340 योग सहायकों की पहले ही नियुक्त किया जा चुका है।

1,100 करोड़ रुपए का बजट : मनोहर लाल ने कहा कि गांवों में विकास कार्यों के लिए पंचायती राज संस्थाओं को 1,100 करोड़ रुपए का बजट इस वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही में दिया गया है। इसमें से 850 करोड़ केवल पंचायतों को दिया गया है। ग्राम पंचायत से प्रस्ताव पारित करवाकर जल्द से जल्द कार्य करवाना सुनिश्चित करें।

नए बाग लगाने के लिए प्रति एकड़ 50 फीसदी अनुदान

हरियाणा सरकार द्वारा परंपरागत खेती में बढ़े हुए जोखिम और लागत को देखते हुए बागवानी को बढ़ावा देने के लिए नित नए प्रयास किए जा रहे हैं। अब नए बाग लगाने पर किसानों को प्रति हैक्टेयर 50 प्रतिशत तक अनुदान दिया जा रहा है। विशेष रुप से जिले में धान के स्थान पर फलों के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने बाग लगाने के लिए विशेष अनुदान योजना शुरू की है।

अनुदान राशि प्रदान की

सामान्य दूरी वाले बागों के लिए जिसमें बेर, चीकू, लीची, आंवला, आडू एवं नाशपति आदि फलों के लिए प्रति एकड़ लगभग 95 पौधे प्रति एकड़ लगाने के लिए 65 हजार प्रति एकड़ के हिसाब से 50 फीसदी 32,500 रुपए का अनुदान प्रदान किया जाएगा, जिसमें प्रथम वर्ष 19,500, द्वितीय और तृतीय वर्ष के लिए 6,500-6,500 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। इसी प्रकार सक्षन बागों के लिए जिसमें आम, अमरुद, नींबू वर्गीय, अनार, आड़ू, अलूचा, नाशपाती, अंगूर, पपीता एवं ड्रैगन फ्रूट आदि फलों के लिए प्रति एकड़ 111 पौधे लगाने के लिए 1 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से 50 हजार रुपए का अनुदान प्रदान किया जाएगा, जिसमें प्रथम वर्ष 30 हजार, द्वितीय व तृतीय वर्ष के लिए 10-10 हजार रुपए की अनुदान राशि प्रदान की जाएगी। टिशु कल्चर खजूर प्रति एकड़ लगभग 63 पौधे लगाने के लिए 2 लाख प्रति एकड़ के हिसाब से 1 लाख 40 हजार का अनुदान दिया जाएगा, जिसमें प्रथम वर्ष 84 हजार और द्वितीय और तृतीय वर्ष में 28-28 हजार रुपए की अनुदान राशि प्रदान की जाएगी।

ऑनलाइन पंजीकरण

पौधा जाल प्रणाली (मुख्यतः अनार, ड्रैगन फ्रूट, अमरुद, अंगूर इत्यादि बागों के लिए) 1 लाख 40 हजार के हिसाब से 70 हजार रुपए का अनुदान प्रदान किया जाएगा। इन योजनाओं के तहत एक किसान अधिकतम 10 एकड़ क्षेत्र में अनुदान प्राप्त कर सकता है। आवेदन हेतू हॉर्टनेट.जीओवी.इन पर पंजीकरण करवाया जा सकता है, अनुदान पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर प्रदान किया जाएगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए 'मेरी फसल-मेरा ब्यौरा' पोर्टल पर पंजीकरण होना अनिवार्य है। सूक्ष्म सिंचाई/ड्रिप सिंचाई प्रणाली का लाभ लेने के लिए मीकाडा.हरियाणा.जीओवी.इन पर आवेदन किया जा सकता है। इस विषय में अधिक जानकारी के लिए संबंधित जिला उद्यान अधिकारी कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।

मत्स्य पालन को बढ़ावा देती योजनाएं

हरियाणा मत्स्य पालन विभाग द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत मत्स्य पालकों को अनेक प्रकार की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। इसके अलावा मत्स्य पालकों को तकनीकी सहायता भी उपलब्ध करवाई जा रही है। मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा अनेक योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं।

तकनीकी सहायता

प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना का उद्देश्य उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि, मत्स्य प्रबंधन और नियामक ढांचा, टेक्नोलॉजी इंफ्यूजन तथा पोस्ट हार्वेस्ट प्रबंधन के लिए ढांचागत सहायता प्रदान करना है। योजना के तहत तकनीकी सहायता भी उपलब्ध करवाई जाती है। इनमें मछली पालन के लिए पट्टे पर गांव के तालाबों को प्राप्त करना, मछली संस्कृति इकाई के निर्माण के लिए ऋण, प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था, तालाब स्थलों की मिट्टी एवं पानी की जांच, योजना और तालाबों के अनुमान की तैयारी, गुणवत्ता वाले बीज और फीड की आपूर्ति, मछली के विकास की जांच, मछली के रोगों की जांच आदि शामिल है।

वित्तीय सहायता

योजना के तहत मत्स्य पालन विभाग द्वारा इस क्षेत्र में विभिन्न गतिविधियों के लिए किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। सघन मत्स्य विकास कार्यक्रम की योजना का उद्देश्य नए तालाबों की खुदाई, मछली संस्कृति के लिए सामुदायिक भूमि का नवीनीकरण करके अतिरिक्त जल क्षेत्र का निर्माण करना, मौजूदा तालाबों और सूक्ष्म जल क्षेत्रों में मछली संस्कृति को बनाएं रखने के लिए मछली किसानों को तकनीकी सहायता प्रदान करना है। इंटेंसिव फिसरीज स्कीम के तहत भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके अंतर्गत एरियटर की स्थापना पर अनुदान के तहत वास्तविक लागत सीमा 40,000 रुपए प्रति हैक्टेयर पर 50 प्रतिशत तक लाभार्थियों को अनुदान प्रदान किए जाने का प्रावधान है।

- संवाद ब्यूरो

हरियाणा सरकार ने गरीब परिवारों को सरसों के तेल के लिए मिलने वाली राशि में 50 रुपए की बढ़ोतरी की है। इससे राज्य के 31.47 लाख परिवारों को लाभ मिलेगा।

दुष्यंत चौटाला ने नागरिक उड्डयन विभाग को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश की सभी एयर-स्ट्रिप्स पर एटीएस और फायर-सिस्टम लगाया जाए। इससे एयर स्ट्रिप्स पर प्लेन सुरक्षित खड़े हो सकेंगे।

चीनी मिलों में घाटे के बावजूद गन्ने के भाव में बढ़ोतरी

» मूल्य 362 रुपए से 372 रुपए प्रति क्विंटल

» सरसों की नियमित गिरदावरी 5 फरवरी से

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गन्ना किसानों के हित में गन्ने के मूल्य में 10 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की घोषणा की है। बढ़ोतरी के बाद अब गन्ने का मूल्य 362 रुपए से 372 रुपए हो गया है, जो इसी पिराई सत्र से लागू होंगे।

मुख्यमंत्री ने किसानों से अपील की है कि चूंकि गन्ने के भाव में वृद्धि की गई है, इसलिए अब किसान गन्ने को मिलों में ले जाना शुरू करें, ताकि मिलें सुचारू रूप से चल सकें। चीनी मिलों का बंद होना न तो किसानों के हित में है और न ही मिलों के।

उन्होंने कहा कि हालांकि चीनी की मौजूदा कीमत उम्मीद के मुताबिक नहीं बढ़ी है, फिर भी हम चीनी की कीमत की तुलना में गन्ना किसानों को अधिक कीमत दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि चीनी मिलें लगातार घाटे में चल रही हैं, लेकिन फिर भी हमने समय-समय पर किसानों के हितों की रक्षा की है।

उन्होंने बताया कि इस समय राज्य की चीनी मिलों पर 5293 करोड़ रुपए का घाटा है। सरकारी मिलों में चीनी की रिकवरी का प्रतिशत 9.75 है, जबकि निजी मिलों का प्रतिशत 10.24 है। उन्होंने कहा कि चीनी की रिकवरी बढ़ाने और मिलों को अतिरिक्त आय के लिए मिलों में एथेनॉल और ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के साथ-साथ सहकारी चीनी मिलों की क्षमता बढ़ा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि गन्ने के मूल्य निर्धारण के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की थी, जिसने गन्ना किसान की मांगों पर विचार करने के बाद अपनी रिपोर्ट सौंपी। समिति ने किसानों, सहकारी विभाग, निजी मिलों और विशेषज्ञों के साथ कई बैठकें की हैं और अन्य महत्वपूर्ण सिफारिशों के साथ गन्ने के मूल्य में बढ़ोतरी की सिफारिश की।

उन्होंने कहा कि इस मौसम में सर्दी अधिक पड़ी है, जिसके कारण सरसों की फसल काफी प्रभावित हुई है। नुकसान का आंकलन करने के लिए 5 फरवरी से नियमित गिरदावरी शुरू की जाएगी और जहां-जहां नुकसान हुआ है, किसानों को उचित मुआवजा दिया जाएगा।

गन्ना किसानों को समय पर हो रहा भुगतान

हरियाणा में गन्ना किसानों का समय पर भुगतान किया जाता है। वर्ष 2020-21 में 2628 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है और इस वर्ष को कोई भी बकाया नहीं है। इसी प्रकार, वर्ष 2021-22 में केवल 17.94 करोड़ रुपए नारायणगढ़ चीनी मिल के पीडीसी को छोड़कर 2727.29 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। उन्होंने कहा कि सहकारी चीनी मिलों को निर्देश दिए हुए हैं कि एक सप्ताह के भीतर किसानों को भुगतान किया जाए। उन्होंने कहा कि किसानों को भी ऑफर दी गई है कि यदि वे चीनी मिलों का संचालन करना चाहें तो सरकार इस पर भी विचार कर सकती है।

जलभराव आपदा का होगा स्थाई समाधान

बाढ़ और सूखा राहत बोर्ड की 528 परियोजनाओं के लिए करीब 1100 करोड़ की राशि मंजूर

प्रदेश सरकार ने वर्ष 2026 तक हरियाणा को बाढ़ मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए जिन इलाकों में जलभराव की अधिक समस्या है, उसके स्थायी समाधान के लिए इस वर्ष विशेष प्रोजेक्ट लगाए जाएंगे। इसके अलावा, जल संरक्षण और बरसात के पानी का दोबारा उपयोग करने के लिए भी अधिक से अधिक जोर दिया जा रहा है। इससे बाढ़ की स्थिति से निपटने के साथ-साथ ग्राउंड वाटर रिजार्जिंग व सूखे क्षेत्रों में पानी का सदुपयोग किया जा सकेगा। इसके लिए सूखा राहत एवं बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की बैठक में 528 परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसके तहत लगभग 1100 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल हरियाणा राज्य सूखा राहत एवं बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की 54वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेतों में खड़े पानी की निकासी और पानी के दोबारा इस्तेमाल के लिए 312 करोड़ रुपए से ज्यादा की योजनाएं अनुमोदित की हैं। इस बार जलभराव की निकासी के लिए क्लस्टर एप्रोच के माध्यम से योजनाएं तैयार की गई हैं। भिवानी जिले को एक क्लस्टर माना गया है, जिसके तहत 8 गांवों कुंगड़, जटाई, धनाना, बढेसरा, सिवाड़ा, प्रेमनगर, घुसकानी, ढाणी सुखन के आबादी एरिया व जलभराव वाले इलाकों में एचडीपीई पाइपलाइन बिछाई जाएगी। इस पर लगभग 16 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि खर्च होगी। इससे लगभग 2 हजार एकड़ जलभराव वाली भूमि से पानी की निकासी होगी।

इसके अलावा, 3 गांवों सिंघवा खास, पुठ्ठी, मदनहेड़ी को मिलकार एक योजना बनाई गई है, जिस पर 9.31 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। इससे लगभग 1500 एकड़ जलभराव वाली भूमि से पानी की निकासी होगी। इसी प्रकार, लगभग 4 करोड़ रुपए की लागत की एक ओर योजना बनाई गई है, जिसके क्रियान्वित होने से 885 एकड़ जलभराव वाली भूमि से पानी की निकासी होगी।

इसी प्रकार, जिला हिसार को क्लस्टर मानकर 3 गांवों भाटोल जाटान, रांगड़ान और खरकड़ा के खेतों से पानी की निकासी के लिए 3.20 करोड़ रुपए की योजना अनुमोदित की गई है। इससे लगभग 750 एकड़ जलभराव वाली भूमि का सुधार होगा। इसके अलावा, खरबला गांव के लिए भी 2.50 करोड़ रुपए की योजना को भी अनुमोदित किया गया है। जिला रोहतक के लिए भी अलग से योजनाओं को मंजूरी दी गई है।

झीलें बनाने की करें योजना तैयार

जहां बहुत ज्यादा जलभराव होता है, ऐसी भूमि पर झीलें बनाई जा सकती हैं। सीएम ने कहा विशेषकर एनसीआर जिलों में लगभग 100 झीलें बनाने की एक योजना तैयार की जाए। इन झीलों के बनने से जलभराव की समस्या का भी स्थायी सामाधान होगा और भू-जल रिचार्जिंग की क्षमता भी बढ़ेगी। इन झीलों को बनाने के लिए किसानों से उनकी जलभराव वाली भूमि के प्रस्ताव मांगे जाएंगे। क्षेत्रवार भूमि का अध्ययन करवाया जाए कि किस प्रकार की भूमि या किस इलाके में कितने सेंटीमीटर तक बारिश का पानी जमीन सोख सकती है।

सरकार जमीन लेने को तैयारः सीएम

मुख्यमंत्री ने कहा कि साल में दो बार जनवरी और मई माह में हरियाणा राज्य सूखा राहत एवं बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की बैठक होनी तय की गई है। जल संरक्षण और पानी के दोबारा उपयोग के लिए भी पिछली बार के 35 करोड़ रुपए के बजट को 167 करोड़ रुपए तक बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि आबादी और कृषि क्षेत्र में जमा हो रहे पानी को ड्रेन आउट करने की बजाय रिचार्ज करने पर बल दिया जा रहा है। 50 एकड़ से ज्यादा एरिया में पानी खड़ा होता है, वो जमीन सरकार लेने को तैयार है। उस जगह पर तालाब या रिचार्ज वेल बनाने का काम करेंगे।

रिचार्जिंग बोरवेल के लिए बनाई नई योजना

जल की उपलब्धता आज के समय में एक बड़ी चुनौती है। इसके लिए जल संरक्षण ही एक मात्र समाधान है। इसी दिशा में भू- जल रिचार्जिंग के लिए सरकार द्वारा जिलों में रिचार्जिंग बोरवेल लगाए जा रहे हैं। एक कदम ओर आगे बढ़ते हुए सरकार ने एक नई योजना बनाई है, जिसके तहत किसान अपनी भूमि पर रिचार्जिंग बोरवेल लगा सकता है। इसके लिए किसानों से आवेदन मांगे गए थे। अब तक 20 हजार किसानों के आवेदन आ चुके हैं। इन बोरवेल पर सरकार पैसा खर्च करेगी और किसानों से भी कुछ सहयोग लिया जाएगा।

जल संरक्षण और पानी का पुनः उपयोग

जल संरक्षण और पानी के पुनः उपयोग के लिए 97 योजनाओं पर करीब 179 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च की जाएगी। इसके साथ-साथ आबादी प्रोटेक्शन श्रेणी की 67 योजनाओं पर 71.41 करोड़ रुपए, प्रोटेक्शन आफ एग्रीकल्चर लैंड श्रेणी में 125 योजनाओं पर 132.86 करोड़ रुपए, डीवॉटरिंग मशिनरी श्रेणी में 49 योजनाओं पर 77.90 करोड़ रुपए, रिक्लेमेशन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड श्रेणी की 68 योजनाओं पर 119.50 करोड़ रुपए तथा रिकंस्ट्रक्शन, ड्रेनों में पानी के समुचित बहाव के लिए मरम्मत व नए स्ट्रक्चर बनाने के लिए 59 योजनाओं पर 110 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि मंजूर की गई है। इसी प्रकार हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण तथा अटल भूजल योजना के तहत 63 योजनाओं पर 167 करोड़ रुपए की राशि मंजूरी की गई है।

10 जिलों पर विशेष ध्यान

आमतौर पर 10 जिलों नामतः रोहतक, झज्जर, भिवानी, हिसार, जींद, फतेहाबाद, सोनीपत, कैथल, पलवल और सिरसा में जलभराव की समस्या देखने को मिलती है। इसलिए इन 10 जिलों पर विशेष ध्यान देते हुए अधिकतर योजनाएं अनुमोदित की गई हैं।

- संवाद ब्यूरो

'मुख्यमंत्री विवाह शगुन' योजना का लाभ पात्र लाभार्थियों को विवाह के ऑनलाइन पंजीकरण के बाद दिया जाएगा। विवाहिता की शादी का ई-दिशा पोर्टल पर पंजीकरण होना अत्यंत आवश्यक है।

हरियाणा सरकार ने केंद्र की ओर से कुल प्रस्तावित 259 सड़कों को स्वीकृत किया है। इन पर कुल 2,496 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 1,918 करोड़ की लागत से सड़कों का निर्माण कर दिया गया है।

रोज़गार के द्वार खोलती कौशल शिक्षा

श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय द्वारा प्रदेश में सबसे पहले शुरू किए गए इनोवेटिव स्किल स्कूल की तर्ज़ पर प्रदेश के सभी जिलों में इनोवेटिव स्किल स्कूल खोले जाएंगे। इसके माध्यम से नई शिक्षा नीति के अनुसार केजी से पीजी तक स्किल एजुकेशन के लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकेगी।
-मनोहर लाल, मुख्यमंत्री, हरियाणा

यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं की प्लेसमेंट बढ़ाने के उद्देश्य से उच्चतर शिक्षा संस्थानों के मुखियाओं को अधिक से अधिक उद्योगों के साथ एमओयू साइन करने पर विचार किया जा रहा है। इससे अधिक युवाओं को नौकरी मिलेगी।
-मूलचंद शर्मा, उच्चतर शिक्षा मंत्री, हरियाणा

कॉलेजों में जल्द होगी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती

हरियाणा सरकार द्वारा जल्द ही कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती की जाएगी। इसके लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उच्चतर शिक्षा विभाग के अधिकारियों को जल्द हरियाणा लोक सेवा आयोग को मांग पत्र भेजने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने यह निर्देश हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए दिए।

विश्वविद्यालयों व कॉलेजों के शिक्षकों को पुरस्कार

उल्लेखनीय प्रर्दशन करने वाले स्कूल शिक्षकों को दिए जाने वाले पुरस्कारों की तर्ज़ पर विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों के शिक्षकों के लिए भी पुरस्कार दिए जाएंगे। इसके लिए एक योजना तैयार की जाएगी। इसके अलावा, शिक्षा स्तर की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के शिक्षकों के लिए ऑनलाइन मॉड्यूलर ट्रेनिंग प्रोग्राम (ऑनलाइन कंटेंट प्रोडक्शन एंड टीचिंग मैथड) लागू करने का भी निर्णय लिया गया। यह ट्रेनिंग मॉड्यूल श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किया गया है।

2025 तक हरियाणा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति

मुख्यमंत्री ने कहा कि नई शिक्षा नीति में समावेशी और समान गुणवत्तायुक्त शिक्षा उपलब्ध करवाने तथा शिक्षा के अवसरों को बढ़ाने पर बल दिया गया है। हरियाणा में इस नीति को लागू करने के लिए नीति संबंधी मामलों पर सलाह देने, प्लानिंग व रिपोर्टिंग के लिए एडवाइजरी कमेटी बनाई है। नई शिक्षा नीति के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए राज्य सरकार ने एनईपी-2020 को वर्ष 2025 तक प्रदेश में पूर्ण रूप से लागू करने का लक्ष्य रखा है।

हरियाणा में शिक्षा को रोज़गारपरक बनाने पर विशेष ज़ोर दिया जा रहा है। स्किल एजुकेशन के केजी टू पीजी मॉडल और नई शिक्षा नीति के लक्ष्यों के हरियाणा में लागू करने का निर्णय लिया गया है। इतना ही नहीं, बल्कि हरियाणा प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक कौशल विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कौशल व तकनीकी विकास ही युवाओं के लिए रोज़गार के द्वार खोलती है। यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में प्लेसमेंट सैल के माध्यम से न केवल युवाओं को रोज़गार प्रदान किए जाते है, बल्कि उद्योगों के साथ एमओयू साइन करने पर विचार किया जा रहा है।

कौशल सुधार करेंगे नोवेटिव स्किल स्कूल :

हरियाणा के दस जिलों में श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय की तर्ज़ पर इनोवेटिव स्किल स्कूल खोले जाएंगे। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम तैयार किया गया है। नई शिक्षा नीति में स्किल एजुकेशन और जनरल एजुकेशन के सामंजस्य का मॉडल सुझाया गया है। यह राष्ट्र, समाज और उद्योग की दृष्टि से आदर्श है। श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय ऐसे सभी स्कूलों का संचालन करेगा और नवाचार की श्रेणी में सीबीएसई उन्हें मान्यता देगी। यह अभिनव प्रयोग हरियाणा की स्कूल एजुकेशन में मील का पत्थर साबित होगा।

खुलेंगे रोज़गार के नए द्वार :

स्किल इनोवेटिव स्कूल खुलने के बाद रोज़गार के नए मार्ग प्रशस्त होंगे। इसके माध्यम से विद्यार्थी स्कूल एजुकेशन के दौरान ही कौशल की तरफ़ आकर्षित होंगे और उच्चतर शिक्षा में भी वोकेशनल तथा स्किल एजुकेशन के प्रति रुझान बढ़ेगा। स्किल सेट में आईटी, ऑटोमोटिव, एग्रीकल्चर और टेक्सटाइल डिजाइन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्यूटी वेलनेस, डिजाइन मेकिंग, फाइनेंशियल लिटरेसी, हैंडीक्राफ्ट्स, मास मिडिया, हेल्थ केयर, फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर, फूड प्रोडक्शन व सिक्योरिटी जैसे विषय शामिल हैं।

स्कूल शिक्षा में आईटी:

हरियाणा में 'ई-अधिगम' योजना के अंतर्गत 5 मई, 2022 से प्रदेश के सरकारी स्कूलों के कक्षा 10वीं व 12वीं के विद्यार्थियों व उन्हें पढ़ाने वाले सभी पीजीटीएस को टेबलेट्स वितरित किए जाने की शुरुआत की गई। पांच लाख टैबलेट्स तथा सिम कार्ड का वितरण कर दिया गया है। इस टैब में ही उनकी ई-किताबें प्राप्त होंगी। इसमें विद्यार्थियों को सिम कार्ड के साथ 2 जीबी डाटा प्रतिदिन निःशुल्क उपलब्ध करवाया जा रहा है।

प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष कोचिंग:

राज्य में नये 138 राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बनाये गये। जिनका सीबीएसई से एफिलेशन करवाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त नये 1,418 राजकीय मॉडल संस्कृति प्राथमिक विद्यालय भी बनाये गये। खण्ड स्तर तक विस्तारीकरण किया गया। सुपर 100 कार्यक्रम के अंतर्गत सरकारी स्कूलों के मेधावी विद्यार्थियों को आई. आई.टी,/जे.ई.ई./एन.ई.ई.टी. इत्यादि परिक्षाओं के लिए विशेष कोचिंग उपलब्ध करवाई जा रही है।

रोज़गार मेले से नौकरी:

वर्तमान सरकार के कार्यकाल में कुल 72 कॉलेज खोले गए हैं, जिनमें से 31 राजकीय महाविद्यालय केवल लड़कियों के हैं। राज्य के उच्च शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों हेतु क्रेडिट गारंटी स्कीम लागू की गई। यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं की प्लेसमेंट बढ़ाने के उद्देश्य से उच्चतर शिक्षा संस्थानों के मुखियाओं को अधिक से अधिक उद्योगों के साथ एमओयू साइन करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

रोज़गार उपलब्ध करवाए:

हरियाणा के बेरोज़गार युवकों को रोज़गार के अवसर प्रदान करने के लिए एक रोज़गार पोर्टल 15 जुलाई, 2020 से शुरू किया गया। ''शिक्षित युवा भत्ता और मानदेय योजना'' के तहत पात्र स्नातकोत्तर बेरोज़गारों को 3,000 रुपए तथा पात्र स्नातक बेरोजगारों को 1,500 रुपए तथा बारहवीं पास बेरोज़गारों को 900 रुपए प्रतिमाह बेरोज़गारी भत्ता एवं 100 घंटे कार्य करने के एवज में 6,000 रुपए प्रतिमाह मानदेय प्रदान किया जा रहा है।

-संगीता शर्मा

रूटीन से हटकर भी करें कुछ काम

सुबह से शाम तक वही कार्य, वही लोग, वही राम-राम, वही श्याम-श्याम आदि आदि। सप्ताह भर या महीने भर सबकुछ एक ही ढर्रे पर चलता रहे तो जीवन नीरस सा हो जाता है। बीच-बीच में इस रीति में कुछ बदलाव होता रहे तो जीवन में नया जोश व रोमांच बना रहता है। इसलिए हर एक व्यक्ति को कुछ ऐसे कार्य भी करने चाहिएं जो रोजमर्रा से हटकर हों।

जैसे- सारे काम-धाम छोड़कर कहीं घूमने चले जाएं। अपने परिजनों के साथ जाएं। मस्ती करें। परिवार के साथ न जा सकें तो अकेले ही चले जाएं। दो तीन दिन वहां बीताएं। बदला हुआ वातारवरण मिलेगा, खान पान में परिवर्तन होगा। दूसरी तरह के लोगों से मिलना जुलना होगा। कुछ नया देखने व सुनने को मिलेगा। तनाव दूर होगा।

समय निकालें और अपने परिवार के उन लोगों से मिलें जिनसे बहुत कम मिलना होता है। खासकर बड़े बुजुर्गों से मिलें। कुछ उनकी सुनें और कुछ अपनी बताएं। उनके साथ खाना पीना भी करें। उनकी मदद करें। परिवार के किसी भी सदस्य से नकारात्मक या उपहासी रवैये से बात न करें। हो सके तो गांव में रहने वाले परिजनों से मिलने गांव जाएं। कोई परिजन या दोस्त बहुत दिनों से रूठा है तो उसके पास जाएं या उससे फोन पर मुलाकात करें।

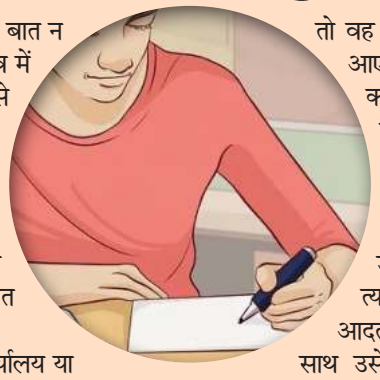

अगर हमेशा कार्यालय या घर के लोगों से घिरे रहते हैं तो अकेले में कुछ समय बिताएं। अपने सारे कार्य खुद करें। खुद को गंभीरता से न लेते हुए अपना खुद का उपहास कर लें। हंस लें। रोने को दिल करे तो रो लें। खुले आसमान के नीचे जाकर आसमान व चारों ओर बिखरी हरियाली व अन्य प्राकृतिक दृश्यों को निहारें। ये सब ईश्वर की रचनाएं हैं। जो मानव के मन बहलाने के लिए ही बनाई हैं। मानव देह में देखते हुए खुद को सौभाग्यशाली मानें। ईश्वर ने आपको सबकुछ दिया है, उसका धन्यवाद करें। परमात्मा से कोई शिकायत है तो वह भी कह डालें। जो मन में आए कहें। मौन रहकर ध्यान करने से भी मन हल्का होता है।

कुछ ऐसा भी किया जा सकता है। जीवन में जो आपको बेहद पसंद है उसका कुछ समय के लिए त्याग करें। कोई खाने पीने की आदत है तो साहस व संयम के साथ उसे छोड़ने का प्रयत्न करें। बल्कि कुछ समय के लिए छोड़ ही दें।

कुछ समय के लिए दिनचर्या को पूरी तरह से बदलने का प्रयास करें। दूर कहीं किसी स्लम बस्ती में जाकर गरीबों की मदद करें। खाना खिलाएं। कोई मरीज मिले तो उसकी दवा-दारू में मदद करें। गोशाला में जाकर गायों को चारा खिलाएं व उनको दुलार करें। ये सब करने के बाद आप खुद को बिलकुल फरिश्ता समान हल्का महसूस करेंगे। जीवन में ताज़गी का अनुभव करेंगे। रूटीन से हटकर ऐसा कर लिया करें।

-मनोज प्रभाकर

सावधान, क्या चल रहा है आपके दिमाग में

मानव जीवन में सोच का बहुत महत्व है। मनुष्य की सोच उसके जीवन की दशा व दिशा तय करती है। सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति अपने जीवन में हमेशा प्रसन्नता से सराबोर रहता है।

स्वामी विवेकानंद के मुताबिक अगर आप आपदाओं के बारे में सोचेंगे तो वह आ जाएंगी। अगर आप मृत्यु के बारे में गंभीरता से विचार करेंगे तो आप अपनी मौत की ओर बढ़ने लगते हैं। अगर आप सकारात्मक सोचेंगे तो विश्वास और निष्ठा के साथ आपका जीवन सुरक्षित हो जाएगा।

विस्टन चर्चिल का कहना था कि किसी निराशावादी को हर अवसर में मुश्किलें दिखाई देती हैं, वहीं आशावादी को मुश्किलों में भी अवसर दिखाई देते हैं। नकारात्मक एवं निराशावादी व्यक्ति हमेशा दुख एवं दर्द के समंदर में डूबा रहता है। नकारात्मक सोच व्यक्ति को अकेला, निस्तेज, उर्जाविहीन एवं निराशावादी बना देती है। कोई व्यक्ति कितना ही फौलादी इरादों वाला एवं उर्जावान क्यों न हो, अगर उसके मन मस्तिष्क में नकारात्मक विचार अपना घर बना लेते हैं तो वह व्यक्ति सामर्थ्यवान होने के बावजूद लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता।

राष्ट्रपति महात्मा गांधी ने सकारात्मक नजरिए पर कहा था कि मनुष्य वह प्राणी है जो अपने विचारों से बना होता है, वह जैसा सोचता है, वैसा ही बन जाता है। सकारात्मक सोच व आशावादी नज़रिए को अपनाकर हम खुद के साथ दूसरों का भी भला कर सकते हैं। सकारात्मक सोच परिवर्तन का आधार है। सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति कभी संसाधनों का रोना नहीं रोता है और सीमित संसाधनों का उपयोग कर अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल रहता है।

इसरो के चेयरमैन के सिवान का संबंध एक गरीब परिवार से था। उनके पिता अखबार बेचकर परिवार का पालन पोषण करते थे। एक साधारण छात्र के पास जितने साधन उपलब्ध होने चाहिएं थे, उसका आधा हिस्सा भी सिवान के पास नहीं था। बावजूद इसके उन्होंने अपनी सकारात्मक सोच की बदौलत जो कर दिखाया, वह सुखी संपन्न एवं सामर्थ्यवान मनुष्य के बस की बात नहीं है। एक आशावादी एवं सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति को पूरा खाली गिलास भी हवा से भरा नज़र आता है, वहीं नकारात्मक एवं निराशावादी व्यक्ति को वह भी नहीं दिखता जो उसकी आंखों के सामने घट रहा होता है। सकारात्मक सोच जीने की एक बेहतरीन शैली है। अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक एवं नज़रिए को स्पष्ट एवं आशावादी रखें।

हरियाणा पुलिस ने अपने अधिकारियों में प्रबंधकीय कौशल विकसित करने के उद्देश्य से भारतीय प्रबंधन संस्थान, रोहतक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

हरियाणा संस्कृत अकादमी द्वारा छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों के प्रोत्साहन के लिए वर्ष 2021-22 के अन्तर्गत छात्रवृत्ति के लिए 43,71,000/- की स्वीकृति प्रदान की है।

उपचार के लिए मिल रही आर्थिक सहायता

राज्य सरकार गरीब लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर अनेक योजनाएं लागू कर रही है ताकि गरीब व्यक्ति भी अपना इलाज़ अच्छे अस्पतालों में करवा सके। 'मुख्यमंत्री राहत कोष' के माध्यम से रोगियों को सीधा लाभ प्रदान किया जा रहा है। हरियाणा सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए गरीब व्यक्तियों को इलाज के लिए तुरंत प्रभाव से लाभ मिले इसको सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने 'मुख्यमंत्री राहत कोष' योजना में संशोधन किया है। अब तीन बिमारियों के इलाज के स्थान पर करीब 25 बिमारियों के इलाज के लिए पीड़ित व्यक्ति को आर्थिक सहायता प्रदान करवाई जा रही है।

कैसे उठाएं सुविधा का लाभ

आर्थिक सहायता के लिए प्रार्थी सरल पोर्टल के माध्यम से सुविधा का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मुख्यमंत्री राहत कोष से मिलने वाली आर्थिक सहायता की राशि सीधे आवेदक या लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। आवेदक अपनी पीपीपी यानी परिवार पहचान पत्र आईडी के माध्यम से सरल पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए आवेदकों को अपने चिकित्सा बिल, ओपीडी बिल आदि जैसे अन्य संबंधित दस्तावेजों को अपलोड कर 'मुख्यमंत्री राहत कोष' से चिकित्सा आधार पर वित्तीय सहायता के लिए आवेदन कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री राहत कोष योजना में किए गए बदलावों के तहत यदि कोई बीमारी 'आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना' में कवर नहीं हो रही है, तो आयुष्मान योजना के लाभार्थियों को भी इस योजना के तहत लाभ मिलेगा। 'मुख्यमंत्री राहत कोष' के अंतर्गत आर्थिक सहायता के लिए जिला स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें संबंधित सासंद, संबंधित एमएलए, उपायुक्त, सिविल सर्जन, नगर परिषद व नगर पालिकाओं के अध्यक्ष, जिला परिषद के चेयरमैन, पंचायत समिति के चेयरमैन को सदस्य और नगराधीश को नोडल अधिकारी बनाया गया है।

मेडिकल दस्तावेज़ों का सत्यापन

आवेदक आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए जब सरल पोर्टल के माध्यम से अपना आवेदन करेगा, उसके बाद आवेदन को संबंधित क्षेत्र के सांसद, विधायक, अध्यक्ष जिला परिषद, अध्यक्ष ब्लॉक समिति, मेयर, एमसी के अध्यक्ष के पास भेजा जाएगा और ये जनप्रतिनिधि पांच दिन के भीतर अपनी सिफारिशों के साथ उपायुक्त कार्यालय को भेजेंगे। उसके उपरांत आवेदन को उपायुक्त कार्यालय द्वारा संबंधित तहसीलदार को आवेदक की चल-अचल संपत्ति की वेरिफिकेशन तथा सिविल सर्जन को मेडिकल दस्तावेजों के सत्यापन के लिए भेजा जाएगा। योजना का लाभ लेने के लिए इस पूरी प्रक्रिया में संपत्ति की वेरिफिकेशन के लिए चार दिन व सिविल सर्जन कार्यालय से जुड़े सत्यापन कार्य के लिए पांच दिन की समय सीमा निर्धारित की गई है। उपरोक्त दोनों विभागों से मिली रिपोर्ट्स को उपायुक्त की संस्तुति के साथ कमेटी के सदस्य सचिव को भेजा जाएगा, जिसे वे सीनियर एकाउंट अधिकारी को भेजेंगे। इसके बाद स्वीकृत की गई राशि सीधे लाभार्थी के खाते में भेज दी जाएगी।

बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मयस्सर कराने में जुटा सेहत विभाग

मनोज प्रभाकर

स्वास्थ्य क्षेत्र में नित नई चुनौतियां और नए शोध आ रहे हैं। ऐसे में आवश्यक है स्वास्थ्य कर्मियों का निरंतर अपडेट रहना। हरियाणा स्वास्थ्य विभाग इस मामले में कोई कंजूसी नहीं बरत रहा है। न केवल चिकित्सकों को बल्कि अन्य स्वास्थ्य कर्मियों को भी अत्याधुनिक सुविधाओं व योजनाओं से अवगत करा रहा है ताकि मरीजों को किसी प्रकार की परेशानी न हो।

विभाग में कार्यरत डाक्टरों, नर्सों व पैरामेडीकल स्टाफ को अपडेट व अपग्रेड करने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यह प्रशिक्षण विभागीय कर्मियों के साथ-साथ मैडीकल कालेजों में कार्यरत सभी डाक्टरों, नर्सों व पैरामैडीकल स्टाफ के लिए भी अनिवार्य किया गया है।

सरकारी डाक्टरों द्वारा प्रत्येक मरीज को दिए जा रहे प्रिसक्रिप्शन का डाटा इंटीग्रेट रखने के लिए कहा गया है। मरीज का कार्ड बनें तथा नियमित मरीज की जांच हो और इस संबंध में एक पुख्ता सिस्टम तैयार किया जा रहा है। इससे जहां, मरीज का डाटा रखने की सुविधा रहेगी और उसका रिकार्ड तुरंत एक क्लिक पर उपलब्ध होगा। इससे अस्पताल व मेडीकल कालेज को अपने स्टॉक को अपडेट करने में भी मदद मिलेगी।

इंटीग्रेटिड हैल्थ लैबारेटरीः

हैल्थ लैबोरेटरी को इंटीग्रेटिड करने के निर्देश स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को दिए गए हैं। आने वाले सालों में हरियाणा में इंटीग्रेटिड हैल्थ लैबारेटरी होगी। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने निर्देश दिए हैं कि हैल्थ लैबोरेटरी में नवीनतम उपकरणों को लगाया जाए और इन लैबोरेटरीज को एनएबीएच से पंजीकृत भी कराया जाए। अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे एनएबीएल के प्रावधानों/विनिर्देशों को ध्यान में रखते हुए गैप को पूरा करें।

मरीजों की डाइट के लिए व्यापक योजना :

अस्पतालों में किचन व मरीजों की डाइट के लिए व्यापक योजना तैयार करनी की योजना है। इसके लिए सभी गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा अस्पतालों में दी जा रही किचन सेवा हेतु डाइटिशन को नियुक्त करना होगा। गौरतलब है कि मेडीकल कालेजों में 85 रूपए में मरीजों को तीन समय का भोजन दिया जाता है, यह डाईटिशन से अनुमोदित होता है। इसी प्रकार, राज्य के अस्पतालों में भी डाइटीशियन चार्ट के अनुसार मरीजों को भोजन वितरित होगा।

इंजीनियरिंग ब्रांच :

स्वास्थ्य केन्द्रों के पुराने भवनों के नवीनीकरण पर ध्यान दिया जा रहा है। योजना के मुताबिक 162 हैल्थ सेंटरों को नवीनतम तरीके से बनाया जाएगा। इसके लिए बडी कंपनियों को काम सौंपा जाएगा ताकि निर्धारित समय अवधि में काम को पूरा किया जा सके। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि स्वास्थ्य विभाग के भवनों के नवीनीकरण, मरम्मत व निर्माण इत्यादि के लिए स्वास्थ्य विभाग व मेडीकल एजूकेशन विभाग इंजीनियरिंग ब्रांच का गठन करें। इसके अलावा, अस्पताल आर्किटेक्ट को भी नियुक्त किया जाए ताकि अस्पतालों की जरूरत के अनुसार निर्माण कार्य को तेजी से आगे बढ़ाया जा सके।

सीटी स्कैन की मशीनें और लगेंगीः

17 जिलों में सीटी स्कैन की मशीन संचालित हो रही हैं। अन्य शेष जिलों में भी यह मशीनें लगाई जाएंगी। एमआरआई की सुविधा पांच जिलों में है, निर्देश हुए हैं कि एमआरआई की मशीनें अन्य जिलों में भी जल्द लगाई जाएं। अल्ट्रासांउड 22 जिलों में संचालित हैं और पीपीपी मोड पर 111 अल्ट्रासांउड मशीनें संचालित की जाएंगी। पीएचसी स्तर पर ईसीजी की सर्विस एक जैसी देने की भी योजना है।

पीएसए प्लांटः

हरियाणा राज्य में पीएसए प्लांट पूरी तरह से संचालित करने के लिए कहा गया है। इनकी सुरक्षा पहलू पर विशेष ध्यान रखा जाए। अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन पर पर्याप्त संख्या में अनुभवी व प्रशिक्षित कर्मियों की डयूटी रोटेशन के अनुसार लगाएं। प्रत्येक 50 बिस्तर से अधिक वाले अस्पतालों व मेडीकल कालेजों में पीएसए से संबंधित कर्मियों की नियुक्ति हो और वहां पर एक डेडेकेटिड होटलाइन भी होनी चाहिए तथा बैक-अप मिलता रहे। जानकारी के मुताबिक मेडीकल कालेजों में 14000 लीटर क्षमता के पीएसए प्लांट स्थापित किए गए हैं।

नशा-मुक्ति (डी-एडीक्शन) केन्द्रः

अवसादग्रस्त मरीजों की सुविधा के लिए मनोवैज्ञानिक काउंसलर की नियुक्ति आवश्यक है। इसके लिए पीजीआईएमईआर, चण्डीगढ के साथ हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग का समझौता हुआ है जिसके तहत पीजीआई के डाक्टर अपनी सेवाएं हरियाणा के मरीजों को देगें। विज ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि 100 बिस्तर से ऊपर वाले सभी अस्पतालों में नशा-मुक्ति (डी-एडीक्शन) केन्द्र होने चाहिए।

एनएबीएच सूचीबद्धताः

हरियाणा में सभी अस्पतालों को एनएबीएच सूचीबद्ध करने के लिए निर्देश दिए गए हैं जिसके तहत राज्य के 500 से अधिक अस्पतालों ने एनएबीएच सूची में अपना पंजीकरण कराया ताकि मरीजों को गुणवत्तापरक सेवाएं प्रदान कर सकें। इसी प्रकार, डब्ल्यूजीएमपी दवाओं को खरीदने का भी एक अभूतपूर्व फैसला किया गया है।

डायलिसिस सेवाएंः

राज्य के 20 जिलों में डायलिसिज सेवाएं दी जा रही हैं। कुरूक्षेत्र में यह सेवा हाल ही में शुरू हुई हैं। मंत्री की ओर से अधिकारियों को निर्देश हुए हैं कि वे डायलिसिस सेंटरों की सख्ती से निगरानी करें और उनके द्वारा अपनाई जा रही सुविधा गुणवत्तापरक होनी चाहिए। रेफरल के संबंध में विज ने कहा कि अब डाक्टर द्वारा मरीज को रेफर करने पर कारण बताना होगा।

सेहत

सूरज की धूप से होती है लंबी उम्र

शरीर में कोशिकाओं की अच्छी सेहत के लिए सूर्य की धूप बहुत आवश्यक होती है। एक अध्ययन के अनुसार सौर ऊर्जा से सक्रिय कोशिकाएं लंबे समय तक स्वस्थ रहती हैं और इससे उनकी उम्र भी बढ़ती है।

जर्नल नेचर एजिंग में प्रकाशित यह अध्ययन राउंड वॉर्म यानी गोल कृमि पर हुआ है। वैज्ञानिकों ने कृमियों में अनुवांशिक बदलाव किए। इस तरह के बदलाव माइटोकोंड्रिया रोशनी को केमिकल ऊर्जा में बदलने के साथ मेटाबॉलिज्म पर भी असर डालते हैं, जिससे राउंड वॉर्म की उम्र को भी बढ़ा हुआ पाया गया। यहां यह जानना जरूरी है कि माइटोकोंड्रिया में गड़बड़ी आने से ही हम जल्दी बूढ़े होते हैं।

हालांकि मनुष्यों पर इस संबंध में काम किया जाना बाकि है। पर इस बात की संभावना जरूर बढ़ी है कि मनुष्यों में भी सोलर एनर्जी से ऊर्जा प्राप्त कोशिकाएं उम्र बढ़ने की प्रक्रिया पर असर डाल सकती हैं। इससे माइटोकोंड्रिया पर और अध्ययन करने और एजिंग के नए तरीके पहचानने में भी मदद मिलेगी।

तंत्रिका तंत्र की मजबूती के लिए सूर्य की किरणें वरदान हैं। प्रतिदिन 20 से 30 मिनट धूप में समय बीतना शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है। इससे कोशिकाएं मजबूत होती हैं तथा शरीर की इम्यूनिटी बढ़ती है।

सलाहः अपने आप को व्यस्त रखें। पौष्टिक भोजन लें। नियमित व्यायाम करें। समय पर सोएं व उठें। धुम्रपान व अन्य मादक पदार्थों के सेवन से दूर रहें। सकारात्मक सोच रखें।

इन लक्षणों को न करें नजअंदाज

अगर आप इन लक्षणों से जूझ रहे हैं तो न्यूरोलोजिस्ट डाक्टर से संपर्क करना चाहिए।

- बांह या पैर का सुन्न हो जाना, उनमें झनझनाहट या भारीपन महसूस करना
- शारीरिक संतुलन बनाए रखने में परेशानी या गिरने का अंदेशा बने रहना
- हाथों से वस्तुओं की पकड़ ढीली रहना
- आंखों पर लगातार दबाव महसूस होना
- चुभता हुआ तेज दर्द होना
- सिर में बार बार तेज दर्द होना, नींद न आना
- बोलने में हिचकिचाहट या अन्य तरह की परेशानी महसूस करना
- बिना श्रम शरीर से पसीना निकलना
- लगातार शारीरिक कमजोरी महसूस करना
- दौरे पड़ना, सिर चकराना, यादाश्त कमजोर होना
- पाचन संबंधी समस्याएं निरंतर रहना

- संवाद ब्यूरो

हरियाणा में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है। इसी दिशा में अब राज्य सरकार का पर्यटन की दृष्टि से विशेष कंट्रोल्ड एरिया चिह्नित करने का भी प्रस्ताव है।

राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने राजभवन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा लिखित पुस्तक 'एग्जाम वॉरियर्स' का विमोचन किया। यह पुस्तक छात्रों के लिए प्रोत्साहन और प्रेरणा का स्रोत रहेगी।

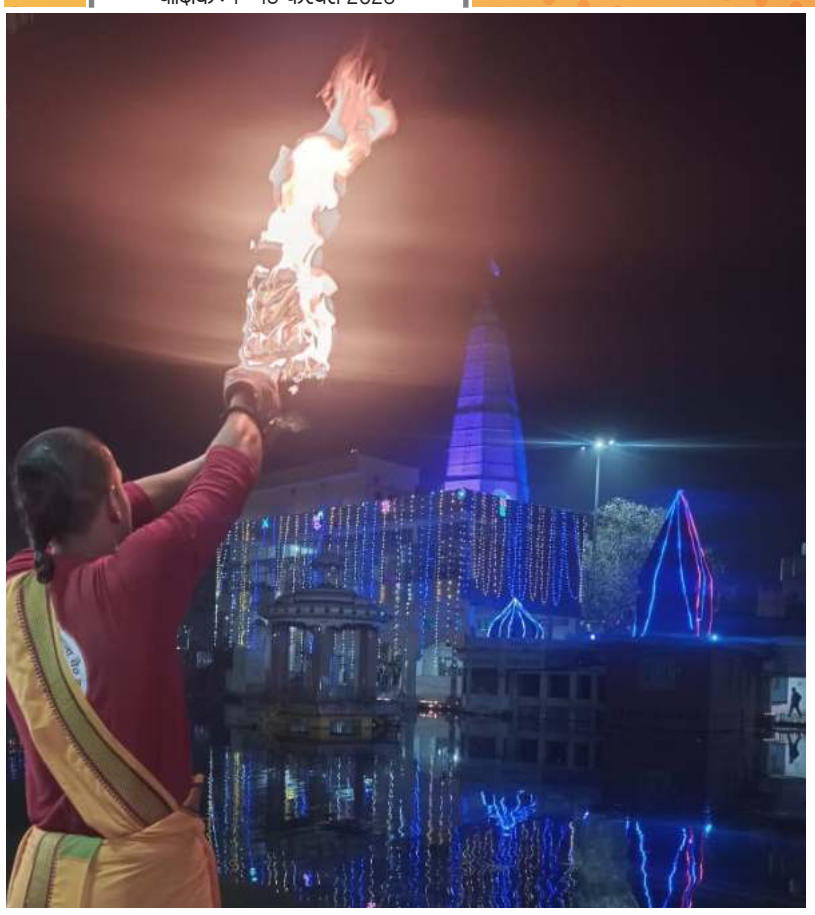

सरस्वती महोत्सव

शंखनाद, मंत्रोच्चारण व आतिशबाजी के साथ सम्पन्न

हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड हरियाणा पर्यटन के लिए लाइफलाइन साबित होगा। आदिबद्री क्षेत्र व सरस्वती उदगम स्थल को पर्यटन की दृष्टि से विश्व के मानचित्र पर लाने के लिए केंद्र व राज्य सरकार द्वारा विशेष कदम उठाए जा रहे हैं। आने वाले समय में हरियाणा के किसानों को सरस्वती जल प्रवाह का बहुत फ़ायदा मिलेगा। हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड द्वारा दो दिवसीय सरस्वती महोत्सव-2023 का आगाज़ 25 जनवरी को आदिबद्री सरस्वती कुंड में 21 कुंडीय हवन यज्ञ से किया गया।

आदिबद्री यमुनानगर में 21 कुण्डीय हवन यज्ञ और मंत्रोच्चारण के बीच अंतरराष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव-2023 का पूरी श्रद्धा और उल्लास के साथ आगाज़ हुआ। महोत्सव में सरस्वती परिक्रमा की गई और मेहमानों ने परिक्रमा करके सरस्वती से जुड़े स्थानों का अवलोकन किया। महोत्सव में शंखनाद के साथ सरस्वती जी की आरती भी की गई। इससे पूर्व सरस्वती शोध संस्थान के संस्थापक, स्वतंत्रता सेनानी एवं पदमभूषण स्वर्गीय दर्शन लाल जैन की प्रतिमा पर सभी महानुभावों ने पुष्प अर्पित किए।

घनश्यामदास अरोड़ा ने कहा कि सरस्वती नदी की धारा को धरातल पर बहाने के लिए बनाई गई कार्य योजना अंतिम चरण में हैं जिसके तहत 341 करोड़ रुपए की राशि से आदिबद्री क्षेत्र में सरस्वती जल भंडारण बांध बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरस्वती देवी बुद्धि, शिक्षा व विवेक की देवी है। उन्होंने कहा कि ऋषि-मुनियों ने सरस्वती नदी के किनारे अनेको धर्म ग्रंथो की रचना की है। उन्होंने कहा कि प्रकृति की स्वाभाविक अदला बदली से सरस्वती नदी लुप्त हो गई जिसे पुनः धरा पर लाया जाएगा जिसके लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री और केंद्रीय जल मंत्रालय प्रय|शील है। उन्होंने कहा कि सरस्वती नदी के किनारे भारत की सभ्यता व संस्कृति विकसित हुई। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिकों ने दोबारा सरस्वती नदी की खोज की और उन्होंने यह सिद्ध कर दिया है कि आदिबद्री में ही सरस्वती नदी का उदगम स्थल है। उन्होंने कहा कि आदिबद्री क्षेत्र में जल भंडारण बांध के साथ माता मंत्रा देवी तक जाने वाला झूला रज्जूमार्ग बनाया जाएगा और इस क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा ताकि आदिबद्री क्षेत्र व सरस्वती नदी का महत्व का सभी का पता चल सके। महोत्सव का 26 जनवरी को समापन हुआ।

उपमंडल पिहोवा में सरस्वती महोत्सव का समापन पर सायंकालीन आरती, शंखनाद व बेहद शानदार आतिशबाजी के साथ हुआ। इस अवसर पर स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज ने सायं की आरती में लोगों को कथा सुनाकर आनंदित किया।

यह महापर्व हमारी संस्कृति का आधार है, जिनसे हमारा सामाजिक रहन-सहन जुड़ा हुआ है। महोत्सव में 21 कुंडीय हवन यज्ञ के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस पवित्र नदी के पावन तट पर हवन यज्ञ और पूजा अर्चना करने पर ज्ञान, शिक्षा, संस्कार की प्राप्ति होती है। इसका उल्लेख ग्रंथों और पुराणों में भी किया गया है। प्राचीन समय में बिमारियों को समाप्त करने के लिए ऋषि-मुनि हवन यज्ञ का आयोजन करते थे।

सुण छबीले बोल रसीले

'तनै सब बातां का बेरा सै'

रसीला आपणी पौली में फोन चलाकै गाण लागर्‌या था- मेरे पाछै-पाछै आवण का भला कौनसा मतबल तेरा सै, होया फिरै बेईमान जले तूं इश्क जाळ नै घेरा सै।। तूं दिखै तो चमक चांदनी, ना तै घोर अंधेरा सै, मनै के पूछै भाभी, तनै सब बातां का बेरा सै।

छबीला आया और लय मिलाकै बोल्या- रसीले आज यू कौणसे रंग का फेरा सै। काम करे तैं कुछ मिलगत होगी, यो मोबाइल के लेर्‌या सै? ..यो तो टाइम खराब करण की मशीन सै।

- भाई रसीले, जिस धोरै फालतू टाइम हो, वो तो खराब करे सकै सै। मनै लागै आजकाल तो सबै धोरै फालतू टाइम सै। यू मोबाइल हाथ में इसा आग्या, अक खेत क्यार के काम नै छोड़के बाकी सारे काम घरां बैठे होज्या सैं। रही सही कसर सरकार नै पूरी कर दी। ऑनलाइन भतेरे काम घरां बैठे होज्या सैं। कितोड़ जाण की जरूरत ना पड़ती। सारे ढाल की खबर इसपै मिलज्या सैं और सारी ढाल के गाने और रागनी भी सुणी जा सकैं सैं। चाहे गली में बैठके सुणले और चाहे सौड़ में मुहं देकै सुण ले।

- बता फेर आजकाल के खबर सै?

- भाई, मनैं इसा लागै सै अक चाचा सीएम ने भ्रष्टाचार के खिलाफ छेड़ी गई जंग तेज कर दी सै। कहने का मतबल भ्रष्टाचार पर प्रहार, चारों ओर हाहाकार।

- ईब मोबाइल में देखर्‌या था, कुछ पंच सरपंच बीडीओ दफ्तर के बाहर ताला लगाण की कोशिश कर रे थे। उनकी पुलिस आळा गेल्यां कहासुणी होगी और हंगामा होग्या।

- पर इसका भ्रष्टाचार तैं के मतबल?

- भाई, मतबल तो कुछ यू ए लागै सै। जो विकास कार्य होंगे, उनके ठेके ऑनलाइन उठैंगे और उन कामां की सारी पेमेंट भी ठेकेदारों को सीधे ऑनलाइन होगी। यानी कम तै कम मोल में ज्यादा से ज्यादा काम। ना कोई बीच बिचोला और ना खर्ची का दाम।

-इस सिस्टम के बारे में कुछेक चौधरी परेशान सैं अक न्यूए होग्या तो वे कितोड़ जावैंगे। उन ताहीं क्यूं सुखे चौधरी बणाया गया? एक दिन सोशल मीडिया पै एक भाई तो न्यूए कहै था कि उसनै सरपंची खातिर डेढ़ करोड़ खर्च दिया। ईब उसनै कोए न्यू पूछणिया हो अक इतणा खर्चा क्यूं और क्यां ताहीं कर्‌या था तो उस धोरै के जवाब होगा? शायद कोय जवाब कोन्या पावै।

भाई छबीले, जै यू सरकार कुछ बरस और न्यूए चाले गई तो राजनीति के पूरे मायने बदल ज्यांगे। पंचायती के अलावा बडे इलेक्शनां में भी लालची आदमियां का आणा बंद होज्यागा। राजनीति का मतबल केवल सेवा रहज्यागा, ज्यूकर दूसरे देसां में व्यवस्था सै अक एमपी हो या मंत्री सब बसां में सफर करैं सैं। छोटी सी तनख्वाह हो सै, भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश नहीं होती।

- पर रसीले, म्हारे आड़ै तो इसा लागै सै जाणु भ्रष्टाचार लोगां के खून में समाया होया सै। बीमारी बहु त गहरी सै। सरकार इसपै अंकुश लगाणे का प्रयास करै सै तो लोग नाराज होज्या सैं।

-ना भाई छबीले, लोग कतई नाराज नहीं होते। आम लोग तो राजी होवैं सैं। नाराज व परेशान केवल वे होवैं सैं जिनकी चालती दुकान खराब होज्या सै।

- सरकार इन दिनां एक साथ कई काम करण लागरी सै। नशे की काली कमाई करण आल्यां की प्रोपर्टी डिगाण लागरी सै। जो गलत तरीके तैं पेंशन लेण लागरे थे, वो काटी जा सैं। जो ब्यौंत आले परिवार सैं उनके बीपीएल कार्ड काटे जा सैं। और जो सरकारी कर्मचारी या अधिकारी तीन दो पांच करैं सैं उनकी गर्दन पकड़ी जा सै।

- तो छबीले, सरकार के इन कामां में गलत के सै? कुछ गलत कोन्या। सरकार एक साफ सुथरी व्यवस्था देणा चाहवै से तो आच्छी बात सै। लोगां नै नाराज होणे की बजाय, सरकार का साथ देणा चाहिए। सीएम सारे प्रदेश नै एक परिवार मानैं सै तो हामनै भी एक परिवार मानकै चालणा चाहिए। किसे की गेल्यां कोय भेदभाव ना हो, सबनै सुख सुविधा मिलैं।

- हां भाई हाम सुखी जिबै रहैंगे, जिब म्हारे अड़ोसी-पड़ौसी, कुणबा और रिश्तेदार सुखी रहैंगे।

- तो भाई गांव में विकास कराण की नीयत सही होणी चाहिए। ई टेंडर व्यवस्था गाम और गाम आळां के हक में है। खाण-पीण के रास्ते बंद, ईब केवल काम का प्रबंध। जन प्रतिनिधियां नै चाहिए कि वे गाम आल्यां गेल्यां मिलकै इतणा विकास करा लें अक आगली बरियां गाम-राम सर्वसम्मति तैं सरपंच बणा दे। इसा मौका सबनै ना मिलता, भागां आळे नै मिल्या करै। जितणी सेवा करोगे, उतणी मेवा पाओगे।

- बस कर रसीले, बस कर। ये पब्लिक है सब जानती है।

-जिबै तो कहूं सूं छबीले, तूं दिखै तो चमक चांदनी, ना तै घोर अंधेरा सै। पब्लिक बोहत है स्याणी, इनै सब बातां का बेरा सै।

-मनोज प्रभाकर

गुड़ की मिठास

सरस्वती नदी के तट पर बसे हरियाणा में न जाने कितनी सभ्यताएं फली-फूलीं, न जाने कितनी कटु-मधुर स्मृतियों को छोड़ अतीत के गर्भ में लुप्त हो गए लेकिन उन सबके जीवन में मिठास घोलता गुड़ आज भी जस का तस विद्यमान है। हरियाणा का हर पर्व-त्यौहार गुड़ के बिना फीका रहता है। गांवों में किसी भी मांगलिक अवसर पर गुड़ से बने गुलगुलों व मालपुओं से कुलदेवता के आगे माथा टेकने के बाद प्रसाद में गुड़ ही बांटा जाता है। तीज-त्यौहारों पर घरों में गुड़ की सुहाली, गुलगुले, मालपुए, गुड़-तिल के लड्डू, गुड़ की पंजीरी बनाई जाती है।

कुछ दशक पहले तक जोट में जुड़े बैलों की घण्टियों की मधुर ध्वनि से पूरा गांव गुंजायमान रहता था। गन्नों की चरड़ाहट और लई में पक रहे रस की खद-बद के मेल से आती निराली धुन मन में भी मिठास घोल देती थी। कृषि जगत में 'क्रान्ति आने के बाद गुड़ ''क्रेशरों' से तैयार होने लगा है, लेकिन गुड़ की मिठास कम नहीं हुई है। खाने के बाद आज भी लोग गुड़ की डली ढूंढते हैं। गुड़ से बनी रेवड़ी, गजक, बड़े चाव से खाते हैं। देसी घी, मूंगफली की गिरी, तिल, मुनक्का, सौंफ, सूखे मेवे वाली गुड़ की डली मिल जाए तो कहना ही क्या!

गुड़ के चार प्रकार माने गये हैं --खुरपा, पाइ, संकर, ढैया। घर में इस्तेमाल के लिए बिना मसाले का गुड़ तैयार किया जाता है। मसालेदार गुड़ में इलायची, सौंफ, काली मिर्च, मूंगफली और नारियल का कस मिला गुड़ प्रायः यह खाने के बाद हाजमा ठीक करने के लिए खाया जाता है।

आयुर्वेद में गुड़ को वात, कफ, पित्त तीनों दोषों का शमन करने वाला है। गठिया, पाचन संबंधी रोगों में लाभप्रद माना जाता है। संस्कृति की अमृत तुल्य मिठास को कायम रखने के लिए गुड़ की भेली को हरियाणा में 'मेल मांढा' नाम दिया गया है।

-प्रमिला गुप्ता

डॉ अमित अग्रवाल, भा.प्र.से. प्रबंध निदेशक, संवाद (सूचना जन संपर्क एवं भाषा विभाग) हरियाणा द्वारा हरियाणा सरकार के लिए कमरा नं. 314, दूसरी मंजिल, लघु सचिवालय, सेक्टर-1, पंचकूला से प्रकाशित।
कार्यालय : संवाद सोसायटी एससीओ 23, पहली मंजिल, सेक्टर 7, चंडीगढ़ फोन : 0172-2723814, 2723812 email : editorsamvad@gmail.com